

uxj ifj"kn Åuk] ftyk Åuk] fgekpy i ns'k ds ys[kkvka dk vad{k.k
, oa fujh{k.k i fronu

vof/k 04@2010 I s 03@2012

Hkkx&, d

1 ¼d½ i kj fHkd %&

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या: 1-376/81-फिन(एल0ए0)खण्ड-IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद ऊना, के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

vad{k.k vof/k ds nkjku vkj.k , oa forj.k vf/kdkjh ds in ij fuEufyf[kr
i /kku rFkk dk; Zdkjh vf/kdkjh dk; j Yk jg%&

i /kku %&

<u>Øetd</u>	<u>uke</u>	<u>vof/k</u>
1	श्रीमती मथुरा देवी	1.4.2010 से 27.1.2011
2	श्रीमती ममता कष्यप	28.1.2011 से 31.3.2012

Dk; Zdkjh vf/kdkjh%&

1	श्री राज किष्ण शर्मा	19.4.2001 से 1.6.2010
2	श्री सुधीर शर्मा	2.6.2010 से 31.3.2012

¼[k½ uxj ifj "kn Åuk ds ys[kkvka vad\$k.k vof/k 4@2010 I s 3@2012 ea i kbZ
xbZ vfu; ferrkvka dk I I kj

Øe I a[; k	vfu; ferrkvka dk I f{klr I kj	i \$k I a[; k	jkf'k yk[kka ea
1	स्वीकृत बजट से अधिक राशि का व्यय	5 (iv)	269.92
2	अग्रिम राशि का समायोजन न करना	5 (v)	4.02
3	NRV योजना के अन्तर्गत Shelters up gradation के लेखाओं से वसूली योग्य राशि	5 (vi)	1.00
4	गृहकर/किराया इत्यादि की राशियों की वसूली हेतु शेष	6.1	42.05
5	विकासात्मक प्रभार की वसूली न करना	6.5	0.83
6	टाऊन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग शुल्क जमा न करना	6.6	45.59
7	सेवानिवृत्त कर्मचारी को अधिक भुगतान	7.1	0.24
8	उपदान का अधिक भुगतान	7.2	5030
9	गलत गणना के कारण संविदाकार को सम्भावित अधिक भुगतान	8.1	0.11
10	गलत लम्बाई दर्शाने के कारण संविदाकार को अधिक भुगतान	8.1.1	0.29
11	गलत गणना के कारण संविदाकार को सम्भावित अधिक भुगतान	8.1.2 2	1.51
12	अधिक दर दर्शाने के कारण संविदाकार को सम्भावित अधिक भुगतान	8.1.3	1.56
13	संविदाकार से आयकर की कम कटौती करना	8.1.4	0.61
14	संविदाकार को अनियमित भुगतान	8.1.5	0.64
15	सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना अतिरिक्त एवं प्रतिस्थापित मदों का निष्पादन	8.1.7	4.77
16	संविदाकार द्वारा निविदा में दी गई दरों को अधिलेखन (overwriting)करके अधिक भुगतान	8.2	0.82
17	सक्षम अधिकारी की अनुमतियों बिना अतिरिक्त मदों का निष्पादन	8.2.1	2.36
18	गलत गणना के कारण संविदाकार को अधिक भुगतान	8.3	0.15

3 वर्षिक लेखा

नगर परिषद ऊना के लेखाओं अवधि 4/2010 से 3/2012 का अंकेक्षण शुल्क ₹40100.00/- आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की राशि सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ऊना के बैंक ड्राफ्ट संख्या 051638 दिनांक 1.11.2012 के माध्यम से निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0 प्र0 षिमला -9 को भेज दी गई है।

4 वित्तीय स्थिति

नगर परिषद ऊना के लेखाओं अवधि 4/2010 से 3/2012 तक की वित्तीय स्थिति परिशिष्ट "i" पर संलग्न है।

बैंक समाधान विवरण:-

दिनांक 31.3.2012 को तैयार किए गए बैंक समाधान विवरण परिशिष्ट (ii) पर दर्शाया गया है।

5 अनुदान

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि 4/2010 से 3/2012 के दौरान प्राप्त अनुदानों का षीर्षवार विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र.सं.	विवरण	क्र.सं.
1	MPLADS	(iii)
2	VKVNY	(iv)
3	Grants received from Deputy commissioner & other Deptt.	(v)
4	Grants received from Tourism Deptt.	(vi)
5	Calamity relief fund	(vii)
6	ULB Roads	(viii)
7	13 th Finance Commission Grant	(ix)
8	EWS grants	(x)
9	SJSRY grants	(xi)
10	EIUS/NSDP	(xii)

11	NFBS grants	(xiii)
12	RGURF grants	(xiv)
13	3 rd SFC grant	(xv)

12614639-44 के अंकुषण अवधि के दौरान परिषिषुत "गअड" डर लगाए गए विवरण के अनुसार विभिन्न डुराडुडुनूँ हेतु डुराडुत अनुदानूँ की राषि ₹12614639.44 करर उडुडुडुग नहीँ किया गया जिसकरर औचितुडु सुडुषुत किया जाए तथर उडुडुडुत राषि कु अनुदानूँ की षुतूँ के अनुसार षुीधुर उडुडुडुग करके उडुडुडुगितर डुरडुडुण डुतुर नुडुडुडुनुसर सडुडुडुधुत विडुडुडुग कु डुरेषुत किए जाए तथर अनुडुडुडुलनर आगरडी अंकुषण डें डुखरई जाए।

12614639-44 के अंकुषण अवधि के दौरान परिषिषुत "गअड" डर लगाए गए विवरण के अनुसार विभिन्न डुराडुडुनूँ हेतु डुराडुत अनुदानूँ की राषि ₹12614639.44 करर उडुडुडुग नहीँ किया गया जिसकरर औचितुडु सुडुषुत किया जाए तथर उडुडुडुत राषि कु अनुदानूँ की षुतूँ के अनुसार षुीधुर उडुडुडुग करके उडुडुडुगितर डुरडुडुण डुतुर नुडुडुडुनुसर सडुडुडुधुत विडुडुडुग कु डुरेषुत किए जाए तथर अनुडुडुडुलनर आगरडी अंकुषण डें डुखरई जाए।

12614639-44 के अंकुषण अवधि के दौरान परिषिषुत "गअड" डर लगाए गए विवरण के अनुसार विभिन्न डुराडुडुनूँ हेतु डुराडुत अनुदानूँ की राषि ₹12614639.44 करर उडुडुडुग नहीँ किया गया जिसकरर औचितुडु सुडुषुत किया जाए तथर उडुडुडुत राषि कु अनुदानूँ की षुतूँ के अनुसार षुीधुर उडुडुडुग करके उडुडुडुगितर डुरडुडुण डुतुर नुडुडुडुनुसर सडुडुडुधुत विडुडुडुग कु डुरेषुत किए जाए तथर अनुडुडुडुलनर आगरडी अंकुषण डें डुखरई जाए।

12614639-44 के अंकुषण अवधि के दौरान परिषिषुत "गअड" डर लगाए गए विवरण के अनुसार विभिन्न डुराडुडुनूँ हेतु डुराडुत अनुदानूँ की राषि ₹12614639.44 करर उडुडुडुग नहीँ किया गया जिसकरर औचितुडु सुडुषुत किया जाए तथर उडुडुडुत राषि कु अनुदानूँ की षुतूँ के अनुसार षुीधुर उडुडुडुग करके उडुडुडुगितर डुरडुडुण डुतुर नुडुडुडुनुसर सडुडुडुधुत विडुडुडुग कु डुरेषुत किए जाए तथर अनुडुडुडुलनर आगरडी अंकुषण डें डुखरई जाए।

12614639-44 के अंकुषण अवधि के दौरान परिषिषुत "गअड" डर लगाए गए विवरण के अनुसार विभिन्न डुराडुडुनूँ हेतु डुराडुत अनुदानूँ की राषि ₹12614639.44 करर उडुडुडुग नहीँ किया गया जिसकरर औचितुडु सुडुषुत किया जाए तथर उडुडुडुत राषि कु अनुदानूँ की षुतूँ के अनुसार षुीधुर उडुडुडुग करके उडुडुडुगितर डुरडुडुण डुतुर नुडुडुडुनुसर सडुडुडुधुत विडुडुडुग कु डुरेषुत किए जाए तथर अनुडुडुडुलनर आगरडी अंकुषण डें डुखरई जाए।

नगर परिषुडु ऊनर करर अवधि 4/2010 से 3/2012 तक करर सुवीकृत डुडुडुत करर वुडुडुडु की गई राषि करर विवरण नुडुडुन डुरकरर थर:-

वर्ष	सुवीकृत डुडुडुत	वररसुतुविक वुडुडुडु	अनुतर
2010-11	21407400	31702970	10295570
2011-12	21773600	38470599	16696999
			26992569

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि नगर परिषद ने 4/2010 से 3/2012 तक स्वीकृत बजट की राशि से ₹26992569/-का अधिक व्यय किया गया। अधिक किए गए व्यय का अनुमोदन/स्वीकृति सक्षम अधिकारी से नहीं ली गई है। अतः म्यूनिसिपल एक्ट 1994 के नियम 251 के अनुसार निदेशक षहरी विकास विभाग का अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त करके व्यय को नियमित करवाना सुनिश्चित करें।

14V½ ₹402482@&vfxæ jkf'k dk l ek; kstu u djus ckj%&

नगर परिषद ऊना द्वारा विभागों को परिषिष्ट "XVII" पर दर्शाए गए विवरणानुसार विभिन्न कार्य के निष्पादन हेतु ₹402482/-की राशि बतौर अग्रिम प्रदान की गई तालिका से यह स्पष्ट है कि अग्रिम राशियों का समायोजन 1974 से नहीं किया जा रहा है। इन राशियों को भुगतान किए हुए लगभग 38 वर्षों का समय हो गया है। अतः मामला निदेशक षहरी विकास हिमाचल प्रदेश व परिषद के सम्बन्धित उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में लाया जाता है तथा षेष बची ₹402482/-समायोजन न करने की स्थान से से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों से अभिलम्ब वसूल करके की राशि परिषद खाते में जमा करवाया जाए क्योंकि यह कार्य पूर्ण हो चुके है।

14Vi½ NRY ; kstuk ds vlrxzr Shelter upgradation ds yunkjka l s ₹100700@&dh jkf'k ol nyh ; kx; 'ks'k%&

कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ऊना द्वारा परिषद परिषिष्ट "xviii" पर लगाए गए विवरणानुसार NRY योजना के अधीन Shelter upgradation विभिन्न लेदनदारों से ₹100700/-दिनांक 31.3.2012 तक वसूली के लिए षेष थी। अतः राशि को सम्बन्धित व्यक्तियों से षीघ्र वसूल करना सुनिश्चित करें।

6 vk; %&

नगर परिषद ऊना की आय के प्रमुख स्रोत निम्न है तथा इनसे प्राप्त आय परिषिष्ट "xix" पर संलग्न है।

6-1 ₹4205870 ol fy; kw 'ks'k%&

नगर परिषद ऊना की विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत निम्नानुसार दिनांक 31.3.2012 तक
₹4205870/-की वसूलियों शेष थी:-

क्र०सं०	विवरण	राशि	परिशिष्ट
(i)	गृहकर	3064385	(xx)
(ii)	दुकान किराया	1106425	(xxi)
(iii)	टावर नवीनीकरण पुलक	35000	(xxii)
		4205970	

6-2 फनुतद 31-03-2012 दक खगदु ₹3064385 धु ओ वुधु 'कुकु&

अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि दिनांक 31.03.2012 को गृहकर के रूप में ₹3064385/-की विभिन्न करदाताओं/भवन मालिकों से वसूल की जानी थसी हिमाचल प्रदेश नगर परिषद अधिनियम 1994 की धारा 87 (प) के अन्तर्गत यदि नगर पंचायत/परिषद को देय कर समय पर प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में टी०एस० 10(ए) में पूर्ण सूचना तैयार करके नगर परिषद के समक्ष आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करना अपेक्षित है तथा दोषी करतादातों के विरुद्ध उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जानी आवश्यक है। इस सम्बन्ध में दोषी तथा काफी लम्बे समय से करों का भुगतान न करने वाले करदाताओं के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई जिसके परिणामस्वरूप नगर पंचायत से क्रिया कलापों पर इसका प्रभाव पड़ा है तथा लम्बित राशियों में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। अतः लम्बित राशि वसूल करने हेतु शीघ्र नियमानुसार आवश्यक/उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

6-2-1 नदुकु@LVkyk ds fdjk, ds : i es fनुतद 31-03-2012 दक जकु'क ₹1106425@&धु ओ वुधु u djuk&

नगर परिषद द्वारा किराए पर दी गई दुकानों/स्टालों के किराए की राशि ₹1106425/-दिनांक 31.3.2012 तक वसूली हेतु शेष थी। कार्यकारी अधिकारी द्वारा किराया वसूली हेतु कोई भी नोटिस जारी नहीं किए गए थे। अतः हिमाचल प्रदेश नगर परिषद अधिनियम 1994 के दिए गए प्रावधानों के अनुसार दुकानदारों को नोटिस जारी किए जाएं तथा

नियम 258 के उप नियम (2) तथा (3) के प्रावधानों के अनुसार किराया न देने वाले दुकानदारों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए।

6-2-2 नजल पकज दीए फु; का }कjk yxk, x, ekckbly Vkoj dh LFkki uk o uohuhdj.k 'kq/d dh ₹35000@&dh ol nyh 'ks'k%&

नगर परिषद क्षेत्र में मोबाईल कम्पनियों द्वारा लगाए गए टावरों की स्थापना व नवीनीकरण शुल्क की ₹35000/- दिनांक 31.3.2012 तक वसूली हेतु शेष थी। अतः इस राशि को शीघ्र वसूल करना सुनिश्चित करें।

6-3 fo | r mi ; kx dj dh ol nyh u djus ckj%&

परिषद द्वारा एक पैसा प्रति यूनिट की दर से विद्युत उपयोग कर की वसूली विद्युत विभाग से की जानी थी। लेखा परीक्षा में पाया गया कि अवधि 2011-12 विद्युत उपयोग कर की वसूली की गई जिसकी वसूली शीघ्र की जाए व अनुपालना आगामी लेखा परीक्षा में बताई जाए।

6-3-1 'kjk dj dh ol nyh u djuk%&

नगर परिषद ऊना द्वारा विभिन्न अवधियों में प्राप्त शराब कर से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया कि अंकेक्षण अवधि में कुल कितनी बोतले शराब बेची गई इस बारे में मामला सम्बन्धित विभाग से शीघ्र उड़ाया जाए तथा उक्त अवधियों के लिए शराब कर की वसूली शीघ्र करके वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

6-4 ₹8100@&dh ol nyh xgLokel l s u djuk%&

मॉग एवं प्राप्ति रजिस्टर के पृष्ठ 100 के अनुसार गृह संख्या 752 के गृहकर की अन्त शेष दिनांक 31.3.2012 तक ₹10125/- बनता था जिसे को दुकान संख्या 589 वर्ष 1999 में नीलामी द्वारा ₹1600/- प्रति माह किराए पर आबंटित की गई परन्तु नगर पंचायत के प्रस्ताव संख्या 159 दिनांक 14.5.2002 द्वारा इस किराए को घटाकर ₹800/- प्रति माह कर दिया गया। किराये को घटाना नगर पंचायत के हितों तथा दुकान आबंटन नियमों के प्रतिकूल था। इस सन्दर्भ में नगर पंचायत के प्रस्ताव संख्या 159 को निदेशक, शहरी विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा पत्र संख्या यू0एल0बी0-एच(ई)(3)-52/2003 दिनांक 9.6.2004 द्वारा रद्द कर दिया गया तथा श्री कमलदेव दुकानदार ने सब जज कोर्ट-III ऊना में इस आदेश के विरुद्ध CMA No. 45/04/03 मामला दर्ज किया। माननीय न्यायालय में दिनांक 18.1.2005 को निर्णय दिया कि

दुकानदार से ₹1600/-प्रतिमाह की दर से किराया वसूला जाए। इन आदेशों के विरुद्ध श्री कमल देव दुकानदार ने जिला सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में मामला दायर किया जिसे कोर्ट ने इस प्रकार निर्णीत किया, "Dismissed as with drawn" इस प्रकार इस प्रकरण में नगर पंचायत द्वारा श्री कमल देव दुकानदार से ₹193014/-लम्बित किराए की वसूली दर्शाई गई है जिसे शीघ्र वसूल करने के अतिरिक्त भविष्य में भी उनसे निर्धारित दर पर ही वसूली की जाए।

दुकान संख्या 514, वर्ष 1998 में श्री सतीष चन्द दुकानदार को ₹600/-प्रतिमाह की दर से किराए पर दी गई। दिनांक 30.5.2009 को यह दुकान श्री अष्वनी प्रभाकर दुकानदार को पुनः आबटित कर दी गई। अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि श्री सतीष चन्द द्वारा कई वर्षों तक किराए का भुगतान नहीं किया गया था। नगर पंचायत द्वारा इस दुकानदार से ₹60292/- किराए की वसूली लम्बित दर्शाई गई है जिसकी वसूली शीघ्र की जाए।

दुकान संख्या 585, श्री हरजिन्द खडवाल को आबटित की गई थी। इस दुकानदार द्वारा नगर पंचायत को कई वर्षों से किराए का भुगतान नहीं किया गया। तहसीलदार ऊना के पत्र संख्या 756-58-रीडर-I दिनांक 5.6.2012 द्वारा "Evilation & Rent Recovery" का मामला निर्णीत किया गया तथा दुकानदार से ₹68365/-की वसूली निर्णीत/घोषित की गई है जिसे सम्बन्धित दुकानदार से शीघ्र वसूला जाए।

नगर पंचायत सन्तोषगढ़ द्वारा एक पैसा प्रति यूनिट की दर से विद्युत उपयोग कर की वसूली की जानी थी परन्तु नगर पंचायत द्वारा अवधि 2011-2012 के लिए विद्युत उपयोग कर की वसूली विद्युत विभाग से नहीं की गई है जिसकी वसूली शीघ्र करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें।

नगर पंचायत सन्तोषगढ़ द्वारा वर्ष 2010-11 के लिए कराधान विभाग से एक रूपये प्रति बोटल की दर से षराब कर की वसूली नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त नगर पंचायत द्वारा अन्यअवधियों में प्राप्त षराब कर किस अवधि से सम्बन्धित था इसका कोई भी उल्लेख

कराधान विभाग द्वारा नहीं किया गया था तथा इस बारे में कोई अभिलेख अंकक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इस बारे में मामला सम्बन्धित विभाग से उठाया जाए तथा अपेक्षित अभिलेख तैयार करने के अतिरिक्त सम्बन्धित अवधियों के लिए शराब कर की वसूली भी करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

1/3 1/2 fcd fdYu 'kY'd dh ol yjh u djus ckj%&

नगर पंचायत सन्तोषगढ़ के परिक्षेत्र में स्थापित ईंटों के भट्टों से वर्ष 2011-12 में कोई भी शुल्क प्राप्त नहीं किया गया जिसके बारे में नियमानुसार कार्रवाई करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए तथा अपेक्षित शुल्क की वसूली भी की जाए।

1/4 1/2 nplkuka ds fdjk; s ea fu; ekud kj c<kfjh u djuk%&

आयुक्त एवं सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या: एल0एस0जी0-एफ(6)-1/85 दिनांक 21.12.2000 के नियम 5 (क) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार 5 वर्ष के उपरान्त किराए में 10% की बढ़ौतरी का प्रावधान है तथा दुकानों से नियमानुसार अनुबन्ध किए जाने हैं परन्तु दुकानों के अनुबन्ध निदेशक शहरी विकास विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार दुकानदारों से नहीं किए गए जिन्हें अब करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें।

1/4 1/2 IDSMT ifj; kstuk ds rgr uofufe'r nplkuka dks fdjk, ij nsus ckj%&

आई0डी0एस0एम0टी0 परियोजना के तहत निम्नानुसार नव निर्मित दुकानों निम्न विवरणानुसार किराए पर दी गई है परन्तु दुकानों के अनुबन्ध निदेशक, शहरी विकास विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार दुकानदारों से नहीं किए गए जिन्हें अब करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

Ø0l Ø	nþku l Ø	nþkunkj dk uke	vkç/u frfk	dh ekfl d fdjk; k
1	2	श्री ब्रजेश शर्मा	5/2011	1400
2	3	श्री ब्रजेश शर्मा	5/2011	1200
3	कैफैटेरिया	श्री राकेश तलवार	12/2011	8000

¼t½ uxj ipk; r }kjk vkfdMDV] tñu; j bJthfu; j] M¼Veñ l s jftLV\$ku
'k¼d@ uohuhdj.k 'k¼d iklr u djus ckj%&

म्यूनिसिपल एक्ट 1994 की धारा 203 के अनुसार नगर पंचायत में जिन आर्किटेक्ट, जूनियर इंजीनियर ड्राफ्टमैन द्वारा नगर पंचायत परिक्षेत्र में निर्मित करवाए जाने वाले भवनों के नक्शे पास करने के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं उनसे रजिस्ट्रेशन शुल्क/नवीनीकरण शुल्क की राशि की वसूली की जानी है परन्तु अंकेक्षण मैमों संख्या 112/2012 दिनांक 08.08.2012 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा इस बारे कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई। अतः इस प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाए।